

WEIGHT THE TENTE OF THE TENTE O

HART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549] नई बिल्ली, बुधवार, सितस्बर 6, 1989/मात्र 15, 1911 No. 549] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT. 6, 1989/BHADRA 15, 1911

इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या वी जाती है जितसे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रवास्थ्य और परिवार अस्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

ध्रिधसूचन।

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1989

का. जा. 698 (म): \rightarrow खाच प्रपिश्रण निवारण भिधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा के खण्ड (IV) के घनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतव्दारा भारत सरकार, स्वान्ध्य और परिवार कत्याण मंत्राक्षय

II

III

IX

2	THI	B GAZETTE (OF INDI
1 के अनुभाग 5 के 3 के स्थान पर निस्क	ह ग्रधीन मकान किराया लिखित सारणी रखी जा	भत्ता के संबंध मे एगी, श्रर्थात्:—	ां, सारणी
	सारणी-3		
(म्कान कि	राया भत्ता की दर (वेत	न का प्रतिशत)	
ब न की वर्ग	20 लाख और 10 से ससे प्रधिककी के बीच व जनसंख्या वाले वाले न	ही जनसंख्या की ज	ा ख से कम नसंख्या वार्ले कस्बे
والمراسط ويسمونون ويرسانهم ويسرونون ومود والمدروب والمراسود	नगर, कस्बे	يو حور دين دون من نيان الله من الله الله الله الله الله الله الله الل	
1	2	3	4
Ia	15	14	13
1	14	1,3	12
II	13	12	11
III	12	11	10
1	11	10	8
V	10	9	8
I	9	8	7
ΤĬ	8	7	6

टिप्पण:-- ऊपर बाणत मकान किराया भक्ते की दर, किसी भी नगर में समाचारपत स्थापन के किसी वर्ग के अधीन कर्मचारियों के किसी समृह के लिए 1200 रुपए के प्रधिकतम के भ्रद्यीन 'रहते हुए होगी।

7

6

(ii) ग्रध्याय 9 के ग्रधीन भाग ! के अनुभाग 5 के ग्रधीन नगर प्रतिकारात्मक भत्ता के संबंध में सारणी IV के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:--

सं रणी-4 नगर प्रतिकारात्मक भता (दर प्रतिमास)

6

5

5

4

स्थापन का वर्गं	20 लाख या उससे ग्रधिक संख्या वाले नगर/कस्बे	10 से 20 लाख के बीच जनसंख्या वाले नगर/कस्वे	4 लाख या उससे ग्रधिक जनसंख्या वाले नगर/कस्बे
1	2	3	4
	₹.	₹.	₹.
Iз	100	75	20
I	75	50	20
m	60	35	20
$\dot{\mathbf{m}}_{-}$	50	36	20

2	3	4
45	30	20
40	30	20
40	30	20
40	30	20
50	30	20
40	30	20
	45 40 40 40 50	45 30 40 30 40 30 40 30 50 30

1 जनवरी, 1988 से आगे की अवधि के लिए पहले से दिया गया मकान किराया भत्ता प्रस्तावित उपांतरणों के श्रधीन जब वे अंतिम रूप से अधिसुचित कर दिए जाएं, अनुज्ञेंय मकान किराया भत्ता के महे समायोजित किया जाएगा।

[सं. एस. 33014/1/89-डब्ल्यू.बी.]

MINISTRY OF LABOUR

NOTICE UNDER WORKING JOURNALISTS AND OTHER NEWSPAPER EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE) AND MISCE-LLANEOUS PROVISIONS ACT, 1955 NEWSPAPER ESTABLISHMENT EMPLO-YEES AND THEIR WORKING JOURNALISTS AND NON-JOURNALIST EMPLOYEES.

New Delhi, the 31st August, 1989

S.O. 684 (E):—Whereas the Central Government by the notifications of the Government of India in the Ministry of Labour Nos. S.O. 527(E) and S. O. 528(E), both dated the 17th July, 1985 constituted two wage boards under section 9 and section 13C of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) under the Chairmanship of Justice Shri U. N. Bhachawat, a retired Judge of the Madhya Pradesh High Court for fixing or revising the rates of wages of working journalists and non-journalist newspaper employees:

And whereas, the said Boards have made their recommendations;

And whereas, the Central Government proposes to make certain modifications to the said recommendations, which in its opinion affect important alterations in the character of the said recommendations:

Now therefore, in pursuance of the proviso to clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the said Act notice is hereby given to all persons

likely to be affected by the following modifications to make their representations in writing within a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public to:

The Secretary to the Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhavan, New Delhi.

Proposed modifications:

(i) For Table III, in relation to the House Rent Allowance under section V of Part I under Chapter IX of the recommendations of the Boards for Working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees, the following Table shall be substituted namely:—

TABLE III

Rates of House Rent Allowance
(Percentage of Pay)

Class of Newspaper Establishment.	Towns with population of 20 lakhs and above.	Cities/ Towns with popula- tion between 10 to 20 lakhs	Cities/ Towns with popula tion of less than 10 lakhs.
ĪA	15	14	13
1	14	13	12
11	13	12	- 11
Ш	12	11	10
TV	11	10	9
V	10	9	8
٧I	9	8	7
VII	8	. 7	.6
VIII	7	6	5
lX	6	5	4

- Note:— The rates of House Rent Allowance mentioned above are subject to a maximum of Rs. 1200/- for any group of employees under any class of newspaper establishment in any city.
 - (ii) For Table IV in relation to City Compensatory Allowance under Section V of Part I under Chapter IX, the following table shall be substituted, namely:—

TABLE IV
CITY COMPENSATORY ALLOWANCE
(Rates per mensum)

Class of	Cities/	Cities/	Cities/ Towns	
Establi-	Towns	Towns		
shment	with popu-	with popu-	with popu-	
	lation of 20	lation bet-	lation of 4	
	lakhs and	ween 10 to	lakhs or	
	above.	20 lakhs.	more.	
والمستحورة التنطيق ويوريده المحدودة المحدودين	Rs.	Rs.	Rs.	
IA	100	75	-20	
I	75	50	20	
II	60	35	20	
\mathbf{III}^{*}	50	30	20	
IV	45	30	20	
V	40	30	20	
VI	40	30	20	
VII	40	30	20	
VIII	40	30	20	
IX -	40	-30	20	

The House Rent Allowance already paid for the period commencing on the 1st day of January, 1988 onwards shall be adjusted against the House Rent Allowance admissible under the proposed modifications as and when finally notified.

INo. S-33014/1/89-W.B.1

श्रम जीवी पत्रकार और ग्रन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते) और प्रकीण उपबन्ध श्रीधनियम, 1955 के श्रुवीन समाचार-एजेंसी नियो-जकों और उनके श्रम जीवी पत्रकारों और 'गैर-पत्रकार कर्मचारियों को नौटिस।

का था 685(अ):—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की श्रिभूजना सं. का श्रा 527(अ) और का श्रा 528 (अ), जो दोनों तारीख 17 जुलाई, 1985 की हैं, श्रम जीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ती) और प्रकीण उपनव्ध. श्रिधिनयम, 1955 (1955 का 45) की धारा 9 और धारा 13ग के श्रधीन श्रम जीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार एजेंसी कर्मचारियों की मजदूरी-दरें निर्धारित या पुनरीक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च त्यायालय के एक सेवा निवृत्त त्यायाधीश न्यत्यमूर्ति श्री यू. एन. बछाबत की श्रध्यक्षता में दो मजदूरी बोर्डों का गठन किया था।

और उक्त बोर्डों ने अपनी सिफारिशें कर दी हैं;

और केन्द्रीय सरकार उक्त सिफारिशों में कुछ उपांतरण करने का प्रस्ताव करती है जी उसके विचार में उक्त सिफारिशों के स्वरूप में महत्व-पूर्ण परिवर्तन करते हैं:--

श्रव, श्रतः, उक्त ग्रिविन्यम की धारा 12 की उपवारा (2) के खंड (क) के परन्तुक के श्रनुसरण में ऐसे सभी व्यक्तियों को जिनके निम्न-लिखित उपांतरणों द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, सूचना दो जाती है कि वे उस तारीख से जिसकी राजपत में प्रकाशित इस श्रीधसूचना की